

माइक्रोफाइनेंस और महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन

डॉ. अरुणिमा पाण्डेय
सहायक आचार्य (समाजशास्त्र)
हरिओम सरस्वती पी. जी. कॉलेज धनौरी,
हरिद्वार, उत्तराखंड

सारांश-

भारत में ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण की दिशा में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups SHGs) एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरे हैं। यह शोध पत्र राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा नाबार्ड (NABARD) द्वारा संचालित SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के संदर्भ में सूक्ष्मवित्त (माइक्रोफाइनेंस) की भूमिका का विश्लेषण करता है। नायला काबीर (Kabeer, 1999) के 'संसाधन-अभिकरण-उपलब्धि' (Resources-Agency-Achievements) सैद्धांतिक ढांचे के आधार पर यह अध्ययन के मुख्य रूप से तीन आयामों आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के अध्ययन पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों पर आधारित इस विश्लेषणात्मक अध्ययन में पाया गया कि SHGs ने बचत की आदत, ऋण तक पहुंच, आय-सृजन गतिविधियों तथा घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायनीय भूमिका निभाई है, किंतु क्षेत्रीय असमानता, अपंजीकरण, अत्यधिक ऋणग्रस्तता की आशंका और पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना जैसी चुनौतियां अब भी विद्यमान हैं। अध्ययन के अंत में इन चुनौतियों के समाधान हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

कुंजी शब्द: स्वयं सहायता समूह (SHGs), माइक्रोफाइनेंस, महिला सशक्तिकरण, (NABARD), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन।

1. प्रस्तावना

भारत जैसे विकासशील देश में, जहां जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक समानता की स्थापना विकास नियोजन के केन्द्रीय चिंतन का विषय रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न सरकारी योजनाओं के बावजूद ग्रामीण महिलाएं, विशेष रूप से निर्धन परिवारों से संबंधित महिलाएं, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच से अधिकांश रूप में वंचित रहीं। इस असमानता को दूर करने के उद्देश्य से भारत में स्वयं सहायता समूह (SHG) जैसी अवधारणा को समाज में स्थापित किया गया। 1970 के दशक में गुजरात में स्थापित सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन (SEWA) के अनुभव और बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक (Grameen Bank) के सूक्ष्मवित्त प्रतिमान से प्रेरणा लेते हुए 1992-93 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने लगभग 500 स्वयं सहायता समूहों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने हेतु एक पायलट परियोजना आरंभ की।

आज यह स्वयं सहायता समूहों की यह पहल विश्व के सबसे बड़े सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम (SHG)

बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) का रूप ले चुकी है, जो 31 मार्च 2024 तक देश के लगभग 17.75 करोड़ परिवारों तक अपनी पहुँच बनाये हुए है, जिनमें से 83.52 प्रतिशत समूह विशुद्ध रूप से महिलाओं के हैं। माइक्रोफाइनेंस, अर्थात् छोटी राशि की बचत, ऋण एवं बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं निर्धन वर्ग को उपलब्ध कराना, केवल एक आर्थिक उपकरण मात्र न होकर, महिला सशक्तिकरण का एक मुख्य आधार है। SHGs में महिलाएं समूह में संगठित होकर नियमित बचत करती हैं, आपस में ऋण का लेन-देन करती हैं और क्रमिक रूप से बैंकों से ऋण प्राप्त कर आय-सृजन गतिविधियों में संलग्न होती हैं। इस प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन के साथ-साथ महिलाओं के आत्मविश्वास, निर्णय-क्षमता और सामाजिक प्रस्थिति में भी परिवर्तन देखा गया है।

इस विषय पर विद्वानों में मतभेद पाया गया है कि माइक्रोफाइनेंस वास्तव में महिलाओं को 'सशक्त' बनाता है, या यह केवल उनकी आर्थिक भूमिका का विस्तार करता है, जबकि अंतर्निहित पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा यथावत बना रहता है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी विमर्श के परिप्रेक्ष्य में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में हुए परिवर्तन का द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

2. साहित्य समीक्षा-

1. **नायला काबीर (Kabeer, 1999)** ने अपने प्रतिष्ठित लेख 'Resources, Agency, Achievements' में सशक्तिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके माध्यम से वे व्यक्ति, जिन्हें चयन करने की क्षमता से वंचित रखा गया था, वह क्षमता पुनः प्राप्त करते हैं। बाद के एक अध्ययन में काबीर (Kabeer, 2005) ने दक्षिण एशिया के अनुभवों के आधार पर यह तर्क दिया कि

माइक्रोफाइनेंस को महिला सशक्तिकरण का 'जादुई समाधान' मानना उचित नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव संस्थागत संरचना, ऋण के उपयोग की प्रकृति और स्थानीय सामाजिक संदर्भ पर निर्भर करता है।

2. **बाली स्वैन एवं वालेंटिन (Bali Swain & Wallentin, 2009)** ने भारत के संदर्भ में किए गए अनुभवजन्य अध्ययनों में पांच राज्यों के आंकड़ों के आधार पर पाया कि SHG सदस्यों में सशक्तिकरण के स्तर में गणनात्मक रूप में सार्थक वृद्धि हुई, जबकि नियंत्रण समूह में ऐसा कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया।
3. **डिनिंगर एवं लियू (Deininger & Liu, 2009)** के विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित अध्ययन में आंध्र प्रदेश के SHGs के दीर्घकालिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए आय, संपत्ति-निर्माण और सामाजिक सहभागिता में उल्लेखनीय सुधार पाया गया।
4. **शर्मा एवं वर्मा (Sharma & Varma, 2008)** ने अपने क्षेत्रीय अध्ययनों में SHGs की उद्यमशील गतिविधियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया का विवेचन किया है।
5. **सुंदरम (Sundaram, 2012)** ने भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में SHGs की भूमिका को रेखांकित किया।
6. **मंजुनाथ (Manjunatha, 2013)** के कर्नाटक-केंद्रित अध्ययन में पाया गया कि SHGs ने ग्रामीण महिलाओं की आय एवं निर्णय-क्षमता में सुधार लाकर ग्रामीण विकास में योगदान दिया।
7. **दास एवं बैश्य (Das & Baishya, 2015)** द्वारा असम के काम रूप जिले के रानी ब्लॉक में किए गए वैक्तिक अध्ययन में पाया गया कि माइक्रोफाइनेंस प्राप्ति के पश्चात

अधिकांश उत्तरदाता महिलाओं की गरीबी में कमी आई तथा उनकी बचत की आदत में उल्लेखनीय सुधार हुआ, यद्यपि बीमा जैसी अतिरिक्त वित्तीय सेवाएं अभी भी सीमित पाई गईं।

8. खान, भट्ट एवं संगमी (Khan, Bhat & Sangmi, 2022) ने हाल के अध्ययन में कश्मीर घाटी के संदर्भ में पाया कि माइक्रोफाइनेंस-समर्थित उद्यमिता महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण का एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है, बशर्ते इसे कौशल विकास एवं बाजार तक पहुंच के साथ जोड़ा जाए।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि जहां अधिकांश अध्ययन SHGs के सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों की पुष्टि करते हैं, वहीं कुछ विद्वान सतर्कता पूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए इसकी सीमाओं की ओर भी संकेत करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन इन दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से समाहित करने का प्रयास करता है।

4. शोध के उद्देश्य

1. भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन के उद्भव एवं विकास का ऐतिहासिक विश्लेषण करना।
2. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (आय, बचत, ऋण तक पहुंच) का अध्ययन करना।
3. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जांच करना।
4. स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित माइक्रोफाइनेंस मॉडल की प्रमुख चुनौतियों एवं सीमाओं की पहचान करना।
5. अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है तथा पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के आधिकारिक प्रतिवेदनों, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के प्रकाशनों, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध लेखों से किया गया है। उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन एवं समुचित विश्लेषण के बाद निष्कर्ष प्रतिपादन का कार्य किया गया है।

6. भारत में स्वयं सहायता समूह आंदोलन: उद्भव एवं विकास

भारत में SHG अवधारणा की जड़ें 1970 के दशक में गुजरात की सेल्फ एम्प्लॉयड वुमैंस एसोसिएशन (SEWA) तथा बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के 'समूह-आधारित उधार' (group lending) प्रतिमान में देखी जा सकती हैं। इसे संस्थागत स्वरूप 1992-93 में तब मिला जब NABARD ने लगभग 500 स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने हेतु SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) की एक पायलट परियोजना आरंभ की। तीन दशकों की यात्रा में यह कार्यक्रम विश्व के सबसे बड़े समन्वित वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के रूप में विकसित हो चुका है। NABARD (2024) के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक देश भर में यह कार्यक्रम लगभग 17.75 करोड़ परिवारों को कवर कर रहा था, जिनमें 83.52 प्रतिशत समूह पूर्णतः महिलाओं के स्वयं सहायता समूह थे।

SHG-BLP के समानांतर, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के पुनर्गठन के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) आरंभ किया गया, जिसे बाद में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) नाम दिया गया। यह

मिशन प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार की कम-से-कम एक महिला सदस्य को SHG के दायरे में लाने के उद्देश्य से कार्यरत है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB, दिसंबर 2023) के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अब तक लगभग 39 लाख SHGs को ऋण प्रदान किया जा चुका था, जिसके अंतर्गत लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए। यह आंकड़े इस बात के परिचायक हैं कि माइक्रोफाइनेंस अब भारत की ग्रामीण विकास रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ बन चुका है।

7. मुख्य विमर्श- यथोचित और पर्याप्त अध्ययन के बाद प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य विमर्श में निम्नलिखित बिंदु समाहित किये गए हैं-

7.1 आर्थिक सशक्तिकरण

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु किये गए अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि SHG सदस्यता का महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं की बचत की आदत एवं ऋण तक महिलाओं की पहुंच पर पड़ा है। नियमित समूह-बचत से महिलाओं में वित्तीय अनुशासन विकसित हुआ है, जबकि समूह-आधारित ऋण गारंटी की अनुपस्थिति में भी यह सदस्यता बैंकों से ऋण प्राप्ति को संभव बनाती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिलाओं की आर्थिक समृद्धि में अपनी विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। सुंदरम (2012) एवं दास व बैश्य (2015) के अध्ययनों में पाया गया कि SHG सदस्यता वाली महिलाओं ने आय-सृजन गतिविधियों, जैसे पशुपालन, सिलाई, खाद्य-प्रसंस्करण तथा लघु व्यापार में सम्मिलित होकर पारिवारिक आय में उल्लेखनीय योगदान दिया है। डिनिंगर एवं लियू (2009) ने अपने आंध्र प्रदेश-केंद्रित अध्ययन में भी SHG सदस्यता एवं संपत्ति-निर्माण के बीच सकारात्मक संबंध पाया। इस प्रकार, माइक्रोफाइनेंस ने वित्तीय समावेशन के दायरे का विस्तार करते हुए ग्रामीण महिलाओं को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इससे महिलाओं के साथ ही

साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि के समृद्ध स्त्रोत बने हैं। महिलाओं ने घर की जिम्मेदारियों के साथ ही अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सक्षम बनी हैं।

7.2 सामाजिक सशक्तिकरण

आर्थिक लाभ के अतिरिक्त, SHGs ने महिलाओं के सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया है। साप्ताहिक अथवा मासिक समूह की बैठकें महिलाओं के लिए एक ऐसा सार्वजनिक मंच प्रदान करती हैं जहां वे स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं पारिवारिक मुद्दों पर खुलकर विचार-विमर्श कर पाती हैं। यह उनके सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण और सकारात्मक परिवर्तन है। शर्मा एवं वर्मा (2008) के अनुसार, इन समूहों में सहभागिता से महिलाओं के आत्मविश्वास तथा सार्वजनिक रूप से बोलने की क्षमता में वृद्धि होती है। इन सभी कारणों से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को व्यापक बल मिला है। बाली स्वेन एवं वालेंटिन (2009) के अनुसार, SHG सदस्य महिलाओं में घरेलू निर्णय-प्रक्रिया, जैसे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य-व्यय एवं संपत्ति संबंधी निर्णय में भागीदारी की मात्रा में नियंत्रण समूह की तुलना में, सांख्यिकीय रूप से अधिक पाई गई। यद्यपि यह सभी परिवर्तन सभी क्षेत्रों के महिलाओं पर समान रूप से लागू नहीं होते, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में सापेक्षिक रूप से सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर निर्णयन और सशक्तिकरण को बल मिला है।

7.3 राजनीतिक सशक्तिकरण

73वें संविधान संशोधन के पश्चात पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों ने SHG सदस्य महिलाओं के लिए स्थानीय शासन में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनेक अध्ययनों में पाया गया है कि SHG की सक्रिय सदस्य महिलाएं पंचायत चुनावों में प्रतिनिधित्व करने तथा ग्राम स्तरीय

निर्णय प्रक्रिया में सहभागी बनने के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। मंजुनाथ (2013) के कर्नाटक-केंद्रित अध्ययन में इस बात की पुष्टि होती है, जिसमें SHG नेटवर्क को ग्रामीण महिलाओं के लिए एक 'सामूहिक आवाज़' निर्मित करने वाले मंच के रूप में वर्णित किया गया है। इन सभी तथ्यों से पता चलता है SHGs ने महिलाओं को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया है इसके साथ ही इन महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग भी प्रशस्त किया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सफलता के नवीन आयाम स्थापित कर समाज और राष्ट्र की समृद्धि में अपना सशक्त योगदान दिया है।

8. चुनौतियां एवं सीमाएं- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख चुनौतियाँ और इसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं-

- क्षेत्रीय असमानता: SHG-BLP का विस्तार दक्षिणी एवं पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक रहा है, जबकि उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में इसकी पहुंच सीमित बनी हुई है।
- अपंजीकरण एवं विश्वास की समस्या: अनेक SHGs औपचारिक रूप से पंजीकृत नहीं हैं तथा पारस्परिक विश्वास पर आधारित होकर संचालित होते हैं, जिससे सदस्यों की बचत की सुरक्षा को लेकर कई बार अनिश्चितता उत्पन्न होती है।
- अत्यधिक ऋणग्रस्तता की आशंका: समय पर ऋण-भुगतान का दबाव कभी-कभी परिवार एवं समूह के भीतर महिलाओं पर नए प्रकार के सामाजिक-संस्थागत नियंत्रण को जन्म दे सकता है (2005)। जब महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) या अन्य सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं से ऋण लेती हैं, तो समय पर किश्त चुकाने का दबाव कभी-कभी उनके लिए नए प्रकार के नियंत्रण और तनाव का कारण बन सकता है यद्यपि ऋण का उद्देश्य उन्हें सशक्त बनाना

रहा है, तथापि ऐसी स्थिति उनके लिए नई प्रकार की चिंता उत्पन्न करती है।

- सतहीपन का जोखिम: कुछ आलोचकों के अनुसार, कई बार महिलाएं SHG से प्राप्त ऋण को उत्पादक कार्यों में न लगा कर व्यक्तिगत कार्यों के लिए खर्च कर देती हैं, ऐसे में यदि ऋण का उपयोग केवल उपभोग-व्यय हेतु किया जाए, न कि उत्पादक गतिविधियों हेतु, तो सशक्तिकरण की प्रक्रिया औपचारिक बनी रह सकती है तथा वास्तविक और आपेक्षित सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाता है।
- पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना: वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के बावजूद, अनेक परिवारों में महत्वपूर्ण निर्णय अब भी पुरुष सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं, जिससे स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रदत्त ऋण का वास्तविक उद्देश्य, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य अधूरा रह जाता है।

9. सुझाव-

1. उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में SHG-BLP के विस्तार हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जानी चाहिए।
2. सभी SHGs का चरणबद्ध औपचारिक पंजीकरण सुनिश्चित कर सदस्यों की बचत को अधिक सुरक्षित बनाया जाना चाहिए।
3. ऋण के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता, कौशल-विकास एवं बाजार-संपर्क जैसी 'माइक्रोफाइनेंस-प्लस' सेवाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे महिलाएं स्वयं के कौशल की वृद्धि करके प्राप्त ऋण का भली भांति उपयोग करें और सशक्त बन सकें।
4. SHG संघों को सुदृढ़ कर समूहों की दीर्घकालिक संस्थागत स्थिरता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
5. केवल आर्थिक संकेतकों तक सीमित न रहकर, सशक्तिकरण के सामाजिक एवं राजनीतिक आयामों, जैसे निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता, के

नियमित मूल्यांकन हेतु सूचकांक विकसित किए जाने चाहिए।

10. निष्कर्ष

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संचालित माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रमों ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बचत की आदत, ऋण तक पहुंच, आय-सृजन गतिविधियों में भागीदारी तथा घरेलू एवं सामुदायिक निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता में हुई वृद्धि इस बात के प्रमाण हैं कि SHG मॉडल ने वित्तीय समावेशन के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी योगदान दिया है। तथापि, नायला काबीर (Kabeer, 2005) के सतर्क दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि माइक्रोफाइनेंस अकेले किसी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी नहीं दे सकता; इसकी सफलता संस्थागत सहयोग, वित्तीय साक्षरता, कौशल-विकास तथा स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अतः भविष्य में SHG कार्यक्रमों को केवल ऋण-वितरण तंत्र तक सीमित न रखकर, समग्र सशक्तिकरण की दिशा में एक व्यापक रणनीति के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची-

1. बाली स्वैन, आर., और वालेंटिन, एफ. वाई. (2009). डज़ माइक्रोफाइनेंस एम्पावर वीमेन? एविडेन्स फ्रॉम सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया। इंटरनेशनल रिव्यू ऑफ़ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, 23(5), 541-556।
2. दास, ई. के., और बैश्य, डी. (2015). रोल ऑफ़ सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन एम्पावरिंग रूरल वीमेन: ए केस स्टडी ऑन
3. डेविलींगर, के., और लियू, वाई. (2009). इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ़ सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया (पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नं. 4884)। वर्ल्ड बैंक।
4. काबीर, एन. (1999). रिसोर्सेज, एजेंसी, अचीवमेंट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन द मेजरमेंट ऑफ़ वीमेन्स एम्पावरमेंट। डेवलपमेंट एंड चेंज, 30(3), 435-464।
5. काबीर, एन. (2005). इज़ माइक्रोफाइनेंस ए 'मैजिक बुलेट' फॉर वीमेन्स एम्पावरमेंट? एनालिसिस ऑफ़ फाइंडिंग्स फ्रॉम साउथ एशिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 40(44/45), 4709-4718।
6. खान, एस. टी., भट, एम. ए., और संगमी, एम. यू. डी. (2022). कैन माइक्रोफाइनेंस-बैंक एंटरप्रेन्योरशिप बी ए होलिस्टिक एम्पावरमेंट टूल फॉर वीमेन? एम्पिरिकल एविडेन्स फ्रॉम कश्मीर वैली, इंडिया। जर्नल ऑफ़ बिज़नेस एंड सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 2(2), 117-136।
7. लोखंडे, एम. ए. (2013). माइक्रो फाइनेंस फॉर वीमेन एम्पावरमेंट: ए स्टडी ऑफ़ सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स-बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इंटरनेशनल सेंटर फॉर बिज़नेस रिसर्च, 2(2)।
8. मंजुनाथ, एस. (2013). द रोल ऑफ़ वीमेन सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ़ कर्नाटक स्टेट, इंडिया। इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज, 2(9), 23-25।
9. मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया / प्रेस इन्फॉर्मेशन

- ब्यूरो। (2023, 6 दिसंबर). दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन: सो फार इन एफवाई 2023-24, 39 लाख एसएचजीज़ गेट लोन, रु. 1.12 लाख करोड़ डिस्बर्स्ड।
10. नायर, ए. (2005). सस्टेनेबिलिटी ऑफ़ माइक्रोफाइनेंस सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स इन इंडिया: वुड फेडरेंटिंग हेल्प? (पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर नं. 3516)। वर्ल्ड बैंक।
 11. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। (2013). माइक्रोफाइनेंस इंडिया: स्टेट ऑफ़ द सेक्टर रिपोर्ट 2013। नाबार्ड।
 12. नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। (2024). स्टेटस ऑफ़ द एसएचजी-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (एज़ ऑन 31 मार्च 2024)। नाबार्ड, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशंस डिपार्टमेंट।
 13. ऑफिस ऑफ़ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंडिया। (2011). सेंसस ऑफ़ इंडिया 2011।
 14. शर्मा, पी., और वर्मा, एस. के. (2008). वीमेन एम्पावरमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ ऑफ़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इंडियन रिसर्च जर्नल ऑफ़ एक्सटेंशन एजुकेशन, 8(1), 46-51।
 15. सुंदरम, ए. (2012). इम्पैक्ट ऑफ़ सेल्फ-हेल्प ग्रुप इन सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ़ इंडिया। आईओएसआर जर्नल ऑफ़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, 5(1), 20-27।